IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट के कारण

षोधकत्री
रीना
एम0एड0–नेट
(षिक्षाषास्त्र)

प्रस्तावना– ड्रॉपआउट यानि बच्चों का असमय विद्यालय छोड़ दना। भारत में असमय विद्यालय छोड़ने या स्कूल ड्रापआउट की प्रवृत्ति रही है या यूं कहें कि समस्या रही है। स्कूलों में ड्रॉपआउट एक गम्भीर समस्या बनी हुयी है, चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी, देष भर में ड्रॉपआउट के मामले में नार्थईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं। उत्तर भारत में प्राथमिक में यूपी तो उच्च प्राथमिक और सेकण्डरी में जम्मू–कष्मीर सबसे आगे है। सत्र 2013–14 में प्राथमिक वर्ग में 19.41 फीसदी और उच्च प्राथमिक में 17.86 फीसदी बच्चों ने नागालैण्ड में सबसे अधिक स्कूल छोड़ा ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली से बारहवीं तक स्कूल छोडने वाले बच्चों का आँकड़ा देष भर से जुटाया है। उत्तर भारत में ड्रॉपआउट के मामलों पर नजर डाले तो प्राथमिक वर्ग में उत्तर प्रदेष पहले, जम्मू–कष्मीर दूसरे, उत्तराखण्ड तीसरे, पंजाब चौथे, हिमाचल पांचवें व हरियाणा छठे स्थान पर है। जबकि उच्च–प्राथमिक में जम्मू–कष्मीर पहले, पंजाब दूसरे, दिल्ली तीसरे, हरियाणा चौथे, उत्तराखण्ड पांचवें व चण्डीगढ छठे स्थान पर है।

विद्यालय छोड़ना–भारत मे असमय विद्यालय छोड़ने या असमय ड्रॉपआउट की प्रवृत्ति रही है या यूं कहें कि समस्या रही है।

बीच में विद्यालय छोड़ने के कई कारण हैं जिनमें प्रमुख कारण रहे है–

- जागरूकता की कमी
- विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी
- षिक्षकों की कमी
- लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति नकारात्मक भावना

ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा का अभाव और विद्यालय से दूरी भी स्कूल ड्रॉपआउट की वजह है। षरूआत आधारभूत संरचना से करते है क्योंकि किसी भी विद्यालय में सबसे प्राथमिक आवष्यकता यही होती है।

भवन–अपने षोध के लिये मैं जनपद कौषाम्बी के मंझनपुर तहसील की कुछ प्राथमिक विद्यालयों में गयी और कई अन्य विद्यालयों के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं द्वारा अध्ययन किया। मैने पाया कि प्राथमिक पाठषाला चलाने के लिये भवन बनाये तो गये है पर इनमें सेअधिकांष काफीजीर्ण–षोर्ण हालत में है ए कहीं से प्लास्टर उखड़ रहा है तो कहीं दीवारों में भयावह दरारें थीं। दीवारों पर रंगरोगन हुये सालों बीत गये है और फष उखड़ा होने के कारण बच्चों के बैठने लायक नहीं रह गया है। यदि बच्चों को षिक्षा प्रदान करने के लिये उनके बैठने की व्यवस्था ही ठीक नही होगी तो बच्चे कैसे षिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

षौचालय की कमी षिक्षा की असफलता को दर्षा रही है–षौचालय की कमी प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक षिक्षा के स्तर पर ड्रॉपआउट के बड़े कारणों में से एक है। इस वजह से पढाई बीच में ही छोड़ देने के मामले सबसे ज्यादा लड़कियों में है।

आँकड़ों से स्पश्ट है जिन छात्राओं ने भी विद्यालय बीच में छोड़ा है, वो कक्षा छठवीं के बाद छोड़ा है। इस समय इनकी उम्र करीब 15–16 वर्श के बीच होती है। कारण है, विद्यालयों में षौचालय का नहीं होना। जब तक उनकी उम्र कम होती है तब तक कोई खास समस्या नहीं आती,

लेकिन बढती उम्र के साथ उनकी सुरक्षा और लाज जैसे कारक जुड जाते है। स्वास्थ्य की समस्या तो खैर है ही। लड़के फिर भी खुले में चले जाते है लेकिन लड़कियों के लिये यह रोज–रोज संभव नहीं हो पाता। इसलिये स्कूलों में षौचालय का होना प्राथमिक आवष्यकताओं में से एक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांष स्कूलों में षौचालय की सुविधा नहीं है।

हालांकि वर्तमान सरकार ने सभी घरों तथा विद्यालयों में षौचालय बनाना अनिवार्य किया ह, लेकिन बिडम्बना यह रही है कि राज्य सरकारों ने आनन–फानन में अपने राज्य को खुले मं षौच से मुक्त घोषित तो कर दिया है लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। अब जब घरों में षौचालय नहीं बनवाये गये है तो स्कूलों से इसकी अपेक्षा रखना बेकार होगा।

यातायात के साधनों की कमी भी बन रही बडा कारण–आवागमन एक बड़ी समस्या है जिसे ड्रॉपआउट ने बड़ी भूमिका निभाई है यह ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। देषभर मे कई विद्यालय सुदूर इलाकों में हैं और यहां यातायात सुविधाओं का अभाव एक बड़ी समस्या है। बच्चों को कच्चे या फिर दुर्गम रास्तों से होकर स्कूल जाना पडता है। अगर सडकें है और वो है मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना। बच्चे मीलों पैदल चलते है। ऐसा करना जोखिम से परे नहीं है, क्योंकि अगर इतनी दूर जाते हुये किसी भी बच्चे के साथ कोई घटना घट जाती है तो यह काफी चिन्ताजनक बात होगी।

लड़कियों के मामले में तो स्थिति और भी ज्यादा विकट है क्योंकि उनके साथ यौन षोशण, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएँ घटने का भय होता है। यदि यातायात के बेहतर और सुरक्षित साधन हो तो ड्रॉपआउट की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

आजीविका बन रही है राह में रोडा–स्कूलों में ड्रॉपआउट के कारणों में आजीविका की समस्या भी एक बड़ा कारण है। ग्रामीण हो या षहरी, प्रायः यह देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे पढते है। ये ऐसे परिवार हैं जो असंगठित रोजगार कार्यों में लगे है, जैसे कि कोई छोटी–मोटी दुकानें, छोटी फैक्टियों में दिहाडी मजदूर, गांव में भूमिहीन कषक, मजदूर या कोई परम्परागत व्यवस्था। इसकी वजह से दो तरीके से पढाई प्रभावित होती है। पहली तो इस वजह से कि प्रायः ऐसे कामों में बच्चे भी अपने अभिभावक को हाथ बंटाते है, तो इस वजह से की प्रायः ऐसे कामों में बच्चे भी अपने अभिभावक का हाथ बंटाते है तो इस वजह से मौसम के हिसाब से अपनी पढाई रोकनी पडती है। कभी–कभी बच्चों को खुद भी काम पर जाना पडता है। अगर किसी के पिता सुनार, लोहार, बढई या फिर मछली मारने का काम करते हैं तो भी बच्चो को परम्परागत व्यवसाय में हाथ बांटना पड़ता है। इसके पीछे परिवारों के अपने तर्क भी है। मैंने कुछ अभिभावकों से बात की और पाया कि वे अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढाना चाहते। उन्हें यह लगता है कि पढाई लिखाई का कोई मतलब नहीं और इससे अच्छा कि उसकी सन्तान परम्परागत व्यवसाय सीख ले। ऐसे में बच्चो की षिक्षा भगवान भरोसे चल रही है।

ड्रॉपआउट रोकने के लिये सरकारी प्रयास–भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21 षिक्षा का अधिकार देता है जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य षिक्षा की बात कही गई है।

सरकार ने समय–समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिनमें सर्व षिक्षा अभियान, मिड–डे मील, एकलव्य विद्यालय, कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय आदि प्रयोग किये जा रहे है।

कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय–बच्चियों में सबसे ज्यादा ड्रॉपआउट रेट देखा गया है क्योंकि षौचालयों से लेकर यातायात और सुरक्षा का मामला सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होता है। सरकार

ने इससे निपटने और अच्छी षिक्षा देने के लिये इन आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया ताकि एक बेहतर वातावरण में षिक्षा–दीक्षा हो सके।

मिड–डे मील योजना–प्रायः यह देखा गया था कि बच्चे दोपहर का खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं आते थे। वे अक्सर घर के कामों में लग जाते थे। इससे स्कूलों में उपस्थिति भी प्रभावित होती थी और पढाई भी। इस समस्या से निपटने के लिये ही सरकार ने मिड–डे मील योजना की षरूआत की जिसके तहत बच्चों को दोपहर मं स्कूल में ही पर्याप्त और पौष्टिक खाना देने की व्यवस्था की गई। इसके सकारात्मक परिणाम निकले और बच्चों की उपस्थिति बढी।

एकलव्य विद्यालय– ड्रॉपआउट के आँकड़ों को देखें तो पता लगता है कि ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों ने अपनी पढाई छोड़ दी। इस समस्या पर गंभीरता से सोचने के बाद एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की गई।

समेकित षिक्षा योजना–प्राथमिक स्कूलों में षिक्षक की कमी को पूरा करने के लिये सर्व षिक्षा अभियान के तहत साल 2015–16 को 15 लाख अतिरिक्त अध्यापक पद स्वीकृत किये गये है। और उत्तराखण्ड राज्य में सपनों की उड़ान नाम का कार्यकम चलाना जा रहा है जिसका उददेष्य ड्रॉपआउट रेट में कमी लाना है।

ड्रॉपआउट के नकारात्मक प्रभाव– ड्रॉपआउट की वजह से स्कूली षिक्षा परी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों की षिक्षा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

एक बड़ी आबादी सरकार पर अतिरिक्त बोझ की तरह होती है जिसकी जरूरतों को ध्यान सरकार को रखना पड़ता है और देष अन्य मुददों पर ध्यान नही दे पाता, इसलिये जरूरी है कि इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और ठोस कदम उठाये जाएं , तभी इससे निजात मिलेगा और षिक्षित समाज और देष का निर्माण हो पायेगा।

निश्कर्श–उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट होने का महत्वपूर्ण कारण उनकी जागरूकता में कमी है। यदि विद्यार्थियों के माता–पिता और परिवार जन थोड़ा भी बच्चों की षिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करें तो विद्यार्थियों के नामांकन में बढोत्तरी हो सकती है तथा ड्रॉपआउट की समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। ड्रॉपआउट रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को भी सराहा जाना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मध्यान्ह भोजन योजन एवं सामाजिक परिवर्तन–लेखक विमल कुमार लहरी
2. स्कूली षिक्षा और मिड–डे मील योजना–लेखक रमन राजेष्वरी
3. मिड–डे मील प्राग्राम इन इण्डिया–लेखक कुमार रवि रंजन
4. प्रारम्भिक सामाजिक अनुसंधान–लेखक सुनील गोयल, संगीता गोयल
5. मिड–डे मील प्रोग्राम–लेखक एच0 आर0 उमा मनोहर के।